

भारत सरकार  
योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1154

दिनांक 09.02.2022 को उत्तर देने के लिए

अटल टिकरिंग लैब्स

1154. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर:

डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषरूप से राजस्थान में वर्ष-वार, राज्य-वार तथा जिले-वार स्थापित अटल टिकरिंग लैब की संख्या कितनी है जो सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित हैं;
- (ख) विशेषरूप से राजस्थान में जनवरी, 2022 की तिथि के अनुसार एटीएल को संवितरित धनराशियों का राज्य-वार तथा जिले-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) आगामी तीन वर्षों हेतु एटीएल की स्थापना हेतु कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है;
- (घ) विशेषरूप से राजस्थान में आगामी वर्ष के लिए पाइपलाइन में राज्य-वार और जिले-वार कितने निजी तथा सरकारी एटीएल स्थापित किए जाने हैं;
- (ङ) मार्च, 2020 के बाद कार्यरत एटीएल की संख्या कितनी है तथा क्या सरकार ने कोविड-19 युग के पश्चात् उनके कार्यकरण की समीक्षा करने हेतु किसी विशिष्ट लेखापरीक्षा तंत्र का विकास किया है;
- (च) क्या स्थापित किए गए लैबों की संख्या, एसटीईएम विषयों में लगे विद्यार्थियों की संख्या तथा प्राप्त परिणामों के संदर्भ में एटीएल पहल अपने उद्देश्यों तथा अधिदेश को प्राप्त करने में सफल रहा; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

- (क) जनवरी 2022 तक, वित्तपोषित अटल टिकरिंग लैबों की कुल संख्या 9,606 है, जिनमें से 503 राजस्थान राज्य में हैं।  
सरकारी और निजी दोनों स्कूलों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक क के रूप में दिया गया है।  
राजस्थान के 503 वित्तपोषित सरकारी और निजी दोनों स्कूलों की जिला-वार और वर्ष-वार सूची अनुलग्नक ख के रूप में दी गई है।
- (ख) प्रत्येक स्कूल को स्थापना और प्रचालन लागत के रूप में पांच वर्ष की अवधि में 20,00,000/- रु. (बीस लाख रुपए मात्र) के सहायता अनुदान की स्वीकृति दी जाती है। सही तरीके से अनुपालन प्रक्रिया को पूरा करने की शर्त पर स्थापना और प्रचालन लागत के रूप में कुल राशि में से

12,00,000/- रु. (बारह लाख रुपए मात्र) का सहायता अनुदान पहली किश्त के तौर पर दिया जाता है। प्रचालन और रखरखाव लागत के रूप में अगले चार वर्षों में 2 लाख रु. प्रत्येक बाद की किश्तों के तौर पर दिए जाते हैं।

अटल टिकरिंग लैबों की स्थापना के लिए अब तक कुल 9,606 स्कूलों को पहली किश्त के रूप में 12,00,000/- रु. की कुल 1152.72 करोड़ रु. की राशि संवितरित की जा चुकी है, जिसमें से 60.36 करोड़ रु. राजस्थान राज्य के 503 स्कूलों को अटल टिकरिंग लैबों के लिए संवितरित किए गए हैं।

अब तक कुल 978 स्कूलों को बाद की किश्त के रूप में 2,00,000/- रु. की कुल 19.56 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है, जिसमें से 86 लाख रु. राजस्थान राज्य के 43 स्कूलों में अटल टिकरिंग लैबों के लिए संवितरित किए गए हैं। संवितरित निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

- (ग) अटल टिकरिंग लैबों के लिए अनन्य रूप से कोई विशिष्ट निधि निर्धारित नहीं की गई है। केंद्र सरकार द्वारा अटल नवाचार मिशन के लिए आबंटित राशि मिशन के तहत सभी कार्यक्रमों के लिए है, जिसमें अटल टिकरिंग लैब भी शामिल है। बजट की उपलब्धता के अनुसार स्कूलों को एटीएल स्थापित करने के लिए वित्तपोषित किया जाता है।
- (घ) अटल नवाचार मिशन को देश भर के स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैबों की स्थापना के लिए अधिदेशित किया गया है, जिनमें से 9,606 को पहले ही वित्तपोषित किया जा चुका है। 10,000 अधिदेशित स्कूलों में से शेष स्कूलों में अटल टिकरिंग लैबों की स्थापना के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन प्रक्रिया चल रही है और अनुपालन की पूर्ति के अनुसार 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा।
- (ङ) मार्च 2020 के बाद अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने के लिए वित्तपोषित स्कूलों की संख्या 1922 है। अभी तक, इन 1922 अटल टिकरिंग लैबों के संचालन की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि, एआईएम ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से स्कूलों को कार्यरत करता है और उनकी निगरानी करता है और एटीएल दिशानिर्देशों के आधार पर समीक्षा करता है। एआईएम स्कूलों के साथ निरंतर संपर्क में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त गतिविधियां और कार्यशालाएं चलाई जाती हैं, मुद्दों का समाधान किया जाता है, एटीएल प्रचलनाधीन रहता है और एटीएल स्कूलों के छात्रों के लिए सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करता है।
- (च) एवं (छ) जी हाँ, एटीएल पहल स्कूली छात्रों के बड़े समुदाय को लाभान्वित करने के साथ-साथ अपने अधिदेश को सफलतापूर्वक पूरा करने के दिशानिर्देशों के अनुसार है। 10,000 अधिदेशित एटीएल स्थापनाओं में से 9,606 को पहले ही वित्तपोषित किया जा चुका है और शेष स्कूलों को धनराशि की उपलब्धता और अनुपालन जांच के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा। एटीएल योजना के तहत साल भर कार्यक्रमों और चुनौतियों का आयोजन किया जाता है जिससे युवा छात्रों को नवीन मनोभाव विकसित करने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्राप्त होता है। इसके लिए एक उदाहरण है एटीएल मैराथन जो अटल नवाचार मिशन की प्रमुख नवाचार चुनौती है, जहां स्कूल अपनी चुनी हुई सामुदायिक समस्याओं की पहचान करते हैं और कार्यशील प्रोटोटाइप के रूप में अभिनव समाधान विकसित करते हैं। नवीनतम डैशबोर्ड डेटा के अनुसार 75 लाख से अधिक छात्र सक्रिय रूप से एटीएल से जुड़े हुए हैं। एटीएल छात्रों द्वारा कई परियोजनाएं बनाई गई हैं जो दर्शाती हैं कि अटल टिकरिंग लैब्स युवा मस्तिष्क में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने में सफल रही हैं। अब तक एटीएल छात्रों द्वारा 12 लाख से अधिक अभिनव परियोजनाएं सृजित की गई हैं।

\*\*\*\*\*

## स्कूलों में वित्तपोषित अटल टिकरिंग लैब्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वार्षिक सारांश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	कुल स्कूल	सरकारी स्कूल	प्राइवेट स्कूल	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	7	0	0	10	10	0	1.2
आंध्र प्रदेश	8	4	68	277	213	120	690	558	132	84.3
अरुणाचल प्रदेश	2	0	4	18	6	1	31	25	6	3.76
असम	10	1	10	174	84	52	331	266	65	39.92
बिहार	5	1	15	49	11	13	94	58	36	11.48
चंडीगढ़	3	2	6	5	2	4	22	14	8	2.7
छत्तीसगढ़	7	2	34	184	74	60	361	290	71	44.3
दादरा और नगर हवेली	0	0	2	1	0	1	4	1	3	0.48
दिल्ली	27	4	38	78	41	10	198	70	128	24.9
गोवा	8	1	2	6	1	2	20	18	2	2.52
गुजरात	8	5	44	275	165	101	598	395	203	73.08
हरियाणा	7	8	34	134	108	119	410	107	303	50.1
हिमाचल प्रदेश	2	0	10	49	34	11	106	50	56	13.04
जम्मू और कश्मीर	2	0	7	30	31	18	88	55	33	10.62
झारखंड	3	0	8	53	28	30	122	60	62	14.78
कर्नाटक	13	5	34	298	227	176	753	529	224	91.96
केरल	18	6	60	165	78	37	364	254	110	45.3
मध्य प्रदेश	5	2	50	229	136	164	586	270	316	70.94
महाराष्ट्र	26	5	106	369	250	240	996	830	166	121.5
मणिपुर	1	2	11	45	9	49	117	45	72	14.2
मेघालय	1	0	6	4	1	1	13	10	3	1.56
मिजोरम	1	2	4	16	1	2	26	17	9	3.16
नागालैंड	0	0	7	13	3	2	25	3	22	3.04
ओडिशा	3	1	31	148	51	84	318	193	125	38.68
पुडुचेरी	1	0	3	11	1	2	18	13	5	2.24
पंजाब	12	4	21	86	33	67	223	84	139	27.34
राजस्थान	6	0	15	198	63	221	503	203	300	61.22
सिक्किम	4	1	4	15	0	3	27	23	4	3.26
तमिलनाडु	21	11	45	315	99	448	939	619	320	114.64
तेलंगाना	6	3	19	125	71	133	357	220	137	43.68
त्रिपुरा	0	0	2	10	2	6	20	20	0	2.42
उत्तर प्रदेश	17	9	46	270	258	342	942	202	740	114.04
उत्तराखंड	4	3	6	34	12	22	81	36	45	9.94
पश्चिम बंगाल	11	7	25	64	25	79	211	171	40	25.74
लद्दाख	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0.24
<b>कुल</b>	<b>243</b>	<b>89</b>	<b>779</b>	<b>3755</b>	<b>2118</b>	<b>2622</b>	<b>9606</b>	<b>5726</b>	<b>3880</b>	<b>1172.28</b>

## राजस्थान के स्कूलों में वित्तपोषित अटल टिकरिंग लैब्स का जिला-वार वार्षिक सारांश

जिला	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	कुल स्कूल	सरकारी स्कूल	प्राइवेट स्कूल
अजमेर	0	0	2	7	1	6	16	6	10
अलवर	1	0	0	11	3	10	25	11	14
बांसवाड़ा	0	0	1	2	2	4	9	3	6
बारां	0	0	2	2	3	1	8	7	1
बाड़मेर	0	0	1	4	2	8	15	10	5
भरतपुर	0	0	2	4	2	10	18	4	14
भीलवाड़ा	0	0	1	10	0	9	20	11	9
बीकानेर	0	0	1	2	2	15	20	5	15
बूंदी	0	0	0	1	1	2	4	3	1
चित्तौड़गढ़	0	0	0	11	2	4	17	8	9
चुरू	0	0	0	16	7	19	42	18	24
दौसा	0	0	0	5	1	9	15	2	13
धौलपुर	0	0	0	1	1	2	4	4	0
झुंजरपुर	0	0	0	5	0	2	7	5	2
फतेहपुर	0	0	0	0	1	0	1	1	0
हनुमानगढ़	0	0	0	3	4	18	25	7	18
जयपुर	2	0	2	16	6	17	43	6	37
जैसलमेर	0	0	1	4	0	3	8	6	2
जालोर	0	0	0	2	2	1	5	2	3
झालावाड़	0	0	0	4	1	0	5	3	2
झुंझुनूं	1	0	0	6	4	17	28	6	22
जोधपुर	1	0	1	7	3	10	22	14	8
करौली	0	0	0	4	1	3	8	4	4
कोटा	0	0	0	8	1	3	12	3	9
नागौर	0	0	0	8	6	12	26	8	18
पाली	0	0	0	5	0	2	7	2	5
प्रतापगढ़	0	0	0	2	1	0	3	2	1
राजसमंद	0	0	0	3	1	1	5	5	0
सवाई माधोपुर	0	0	0	7	0	7	14	9	5
सीकर	0	0	0	11	1	10	22	9	13
सिरोही	0	0	0	5	0	2	7	1	6
श्री गंगानगर	0	0	0	5	3	0	8	4	4
टोंक	0	0	0	13	0	5	18	9	9
उदयपुर	1	0	1	4	1	9	16	5	11
<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>198</b>	<b>63</b>	<b>221</b>	<b>503</b>	<b>203</b>	<b>300</b>